HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt No.....C/769........./ Jabalpur, dated.....22/02/2020.
III-1-5/57

The copy of M.P. Rajpatra dated 16-11-2018 containing amendment in M..P. Civil Court Rules 1961 & M.P. Rules and Orders(Criminal) to :-

01. The District & Sessions Judges/ Principal Judge, Family Court ....
02 The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
03. The Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of Madhya Pradesh;
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt ....
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/Registrar(J-I)/J-II/ Registrar(Examination)/ Registrar (I.L.R.)/ Registrar(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Acadamey, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
09. Joint Registgrar Confdl, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
10. Administrative Officer Checker, High Court of M.P. Jabalpur
10. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
12. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

(B.P. SHARMA)
REGISTRAR(DE)

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 and section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, the High Court of Madhya Pradesh, after obtaining the assent of the State Government, hereby, proposes to make the following further amendment in the "Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961", namely:-

AMENDMENT

In the said rules,

1. For rule 418, the following rule shall be substituted, namely:-

"418. Subject to any law or rules and notifications issued thereunder regarding payment of court fees, the process fee at the rate per Defendant/Respondent/Non-applicant/Accused prescribed by notification by the High Court, shall be deposited and amalgamated with the court-fee, at the time of presentation of a main case. No process fee shall be payable after presentation of the case for any reason whatsoever".

2. After rule 418, the following rule shall be inserted, namely:-

"418 (A). (1) The process fee for ordinary process shall be payable at the flat rate of Rs. 100/- per main case, irrespective of any number of Defendant/Respondent/Non-Applicant but in case of process by registered post or speed post or courier the postal charges shall be paid by the party.".

3. After sub-rule (1) of rule 418 (A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) The postal charge for registered post or speed post or courier service shall be paid by the party within the time stipulated in the order, otherwise within seven days from the date of the order.".

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र. A/3957 जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 सपठित धारा 122 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 व मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. उक्त नियमों में, नियम 418 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"418. न्यायालय शुल्क के संदाय के संबंध में, किसी विधि अथवा नियम तथा उनके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अध्यधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय की अधिसूचना द्वारा निर्धारित आदेशिका शुल्क, प्रति प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/अनावेदक/अभियुक्त की दर से मुख्य प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के समय न्यायालय शुल्क के साथ निक्षिप्त तथा समेकित किया जाएगा। प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् किसी भी कारण से कोई आदेशिका शुल्क देय नहीं होगा।

2. नियम 418 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"418 (क). (1) प्रत्येक मुख्य मामले में, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/अनावेदक की किसी भी संख्या का विचार किए बिना, साधारण आदेशिका के लिए आदेशिका शुल्क रूपए 100/– की समान दर पर देय होगी, परंतु पंजीकृत डाक अथवा स्पीडपोस्ट अथवा कोरियर द्वारा ओदेशिका के मामले में डाक प्रभार पक्षकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।"

3. नियम 418 (क) के उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) रजिस्ट्रीकृत डाक या त्वरित डाक या कूरियर सेवा के लिए डाक प्रभार पक्षकार द्वारा आदेश में नियत समय के भीतर, अन्यथा आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।"

रजिस्ट्रार जनरल
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, after obtaining the assent of the State Government, hereby, proposes to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For Rule 546, the following rule shall be substituted, namely:-

"546. Subject to any law or rules and notifications issued thereunder regarding payment of court fees, the process fee at the rate per Defendant/Respondent/Non-applicant/Accused prescribed by notification by the High Court, shall be deposited and amalgamated with the court-fee, at the time of presentation of a main case. No process fee shall be payable after presentation of the case for any reason whatsoever.".

2. After rule 546, the following rule shall be inserted, namely:-:

"546 (A). (1)The process fee for ordinary process shall be payable at the flat rate of Rs. 100/- per main case, irrespective of any number of Respondent/Non-Applicant/Accused/Witness but in case of process by registered post or speed post or courier the postal charges shall be paid by the party.".

3. After sub-rule (1) of rule 546 (A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) The postal charge for registered post or speed post or courier service shall be paid by the party within the time stipulated in the order, otherwise within seven days from the date of the order.".

4. For rule 547, the following rule shall be substituted, namely:-

"547. Process-fee must be paid in court-fee stamps or by electronic means but not in cash. The stamps shall be affixed to an application or memorandum, as is appropriate, filed in court. The application or memorandum should include the description of the court, the number of the case, the section and the Act under which the offence is punishable, the value of the court-fee stamps affixed, details of the processes to be issued and full particulars, name and addresses of the persons on whom the processes are to be served. If an application is filed it must in addition to the requisite stamps for the process-fees bear such stamps as are necessary for its own validity. No process for the issue of which payment of a fee is required, shall be drawn up until the fee has been paid.".

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 व दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की सहमति उपरान्त, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (अपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 546 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"546. न्यायालय शुल्क के संदाय के संबंध में, किसी विधि अथवा नियम तथा उनके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अध्यधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय की अधिसूचना द्वारा निर्धारित आदेशिका शुल्क, प्रति प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/अनावेदक/अभियुक्त की दर से मुख्य प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के समय न्यायालय शुल्क के साथ निक्षिप्त तथा समेकित किया जाएगा। प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् किसी भी कारण से कोई आदेशिका शुल्क देय नहीं होगा।

2. नियम 546 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"546 (क). (1) प्रत्येक मुख्य मामले में, प्रत्यर्थी/अनावेदक/अभियुक्त/साक्षी की किसी भी संख्या का विचार किए बिना, साधारण आदेशिका के लिए आदेशिका शुल्क रूपए 100/– की समान दर पर देय होगी परंतु पंजीकृत डाक या स्पीडपोस्ट या कोरियर द्वारा आदेशिका के मामले में डाक प्रभार पक्षकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।"

3. नियम 546 (क) के उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) रजिस्ट्रीकृत डाक या त्वरित डाक या कूरियर सेवा के लिए डाक प्रभार पक्षकार द्वारा आदेश में नियत समय के भीतर, अन्यथा आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।"

4. नियम 547 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"547. आदेशिका शुल्क का भुगतान न्याय शुल्क मुद्रांकों के रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किया जाना चाहिए नकद में नहीं। मुद्रांक न्यायालय में पेश किए आवेदन पत्र या ज्ञापन जो समुचित हो पर चिपकाए जाएंगे। आवेदन पत्र या ज्ञापन में न्यायालय का विवरण, मामले का क्रमांक, वह अधिनियम तथा धारा जिसके अंतर्गत वह दण्डनीय हो, चिपकाए गए न्याय शुल्क मुद्रांकों का मूल्य, जारी किए जाने वाली आदेशिकाओं के ब्यौरें तथा जिन व्यक्तियों पर उन आदेशिकाओं का निर्वाह होना है उनके पूर्ण विवरण, नाम तथा पते सम्मिलित होंगे। यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आदेशिका शुल्क हेतु आवश्यक मुद्रांकों के अतिरिक्त ऐसे और मुद्रांक भी होना चाहिए, जो उसकी स्वयं की वैधता हेतु आवश्यक हों। कोई भी आदेशिका जिसके जारी किए जाने के लिए शुल्क का भुगतान आवश्यक हो तब तक नहीं लिखी जाएगी, जब तक शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।"

रजिस्ट्रार जनरल
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय